

प्रतिवेदन

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक अधिगम एवं शिक्षा प्रणाली में नई चुनौतियां

25 अगस्त 2023 को लेडी श्रीराम महाविद्यालय के 'आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ' (आई क्यू ए सी) के तत्वावधान में ' राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक अधिगम एवं शिक्षा प्रणाली में नई चुनौतियां ' नामक विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, अविनाशिलिंगम विश्व विद्यालय की पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् प्रो. शीला रामचंद्रन को प्रस्तावित विषय के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्या प्रो.सुमन शर्मा ने प्रो. रामचंद्रन का परिचय देते हुए उनका शॉल एवं डायरी देकर स्वागत किया; तदोपरांत प्रस्तावित विषय पर प्राचार्या ने बीज वक्तव्य देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।

प्रो. शीला रामचंद्रन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े तमाम बिंदुओं पर अपने विचार श्रोता समुदाय से साझा किए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपयोगिता एवं चुनौतियों को कॉलेज के प्राध्यापकगण के सामने रखा। संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यापक समझ प्रदान करना था। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा; इसके साथ ही प्रो. रामचंद्रन ने रा. शि. नी. के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तनगामी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक प्रसिद्ध कहावत के साथ अपनी बात समाप्त की -'जब बदलाव की हवा चलती है तो आइए हम दीवारें न बनाएं बल्कि पवन चक्कियां बनाएं' प्रो. रामचंद्रन द्वारा दिया गया व्याख्यान ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक था। व्याख्यान सत्र के बाद वार्ता सत्र भी किया गया जिसमें शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

कार्यक्रम के अंत में आई. क्यू. ए. सी की संयोजिका मेघा ढिल्लन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। डॉ. ढिल्लन ने कार्यक्रम की योजना बनाने, समन्वय करने एवं उसे क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हरसिमरत कौर ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुए इस सफल आयोजन ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ को समृद्ध किया बल्कि शैक्षिक सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया।